
International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2231-5063

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho Federal University of Rondonia, Brazil	Mohammad Hailat Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken	Hasan Baktir English Language and Literature Department, Kayseri
Kamani Perera Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka	Abdullah Sabbagh Engineering Studies, Sydney	Ghayoor Abbas Chotana Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]
Janaki Sinnasamy Librarian, University of Malaya	Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania	Ilie Pinteau, Spiru Haret University, Romania
Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	Xiaohua Yang PhD, USA
Anurag Misra DBS College, Kanpur	George - Calin SERITAN Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences AL. I. Cuza University, IasiMore
Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania		

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India	Iresh Swami Ex - VC. Solapur University, Solapur	Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur
R. R. Patil Head Geology Department Solapur University,Solapur	N.S. Dhaygude Ex. Prin. Dayanand College, Solapur	R. R. Yaliker Director Managment Institute, Solapur
Rama Bhosale Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel	Narendra Kadu Jt. Director Higher Education, Pune	Umesh Rajderkar Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik
Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur	K. M. Bhandarkar Praful Patel College of Education, Gondia	S. R. Pandya Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai
Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai	Sonal Singh Vikram University, Ujjain	Alka Darshan Shrivastava Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar
Chakane Sanjay Dnyaneshwar Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune	G. P. Patankar S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka	Rahul Shriram Sudke Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)	Maj. S. Bakhtiar Choudhary Director,Hyderabad AP India.	S.KANNAN Annamalai University,TN
	S.Parvathi Devi Ph.D.-University of Allahabad	Satish Kumar Kalhotra Maulana Azad National Urdu University
	Sonal Singh, Vikram University, Ujjain	

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.net



मध्यप्रदेश के दमोह तथा नरसिंहपुर जिले की कृषि पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के प्रभाव का मूल्यांकन

केशव टेकम , तुलसीराम दयाहर्त

¹व्याख्याता, डॉ. हरीसिंग गौर वि.वि., सागर (म.प्र.)
²सहायक प्राध्यापक, शास. क.ने.क.महा. दमोह (म.प्र.)

सारांश :-मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है तथा रोजगार की दृष्टि से कृषि पर अधिक निर्भर है। कृषि में वर्ष 2006-2007 और 2010-11 के बीच (वर्तमान मूल्यों) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान में लगभग 13.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश सोयाबीन (59 प्रतिशत), चना (39.5 प्रतिशत), दलहन (25.3 प्रतिशत), तिलहन (25.2 प्रतिशत) के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में गेहू का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2011-12 में यह 127.20 लाख मीट्रिक टन था। गेहू की उत्पादकता 2705 किग्रा. प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुई जो वर्ष 2008-09 की तुलना में 42.74 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में औसत ऊर्जा उपभोग 0.85 किलोवाट प्रति हेक्टेयर है। प्रदेश में कुल सिंचाई क्षेत्र 2011-12 में 16.35 लाख हेक्टेयर हो गया जिसमें 9 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। सामान्य वर्षा की स्थिति 911.9 मि.मी. जो वर्ष 2012 में 992.4 मि.मी. थी वर्षा में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रस्तावना :-

प्रदेश में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 104.05 लाख हेक्टेयर है जो 2012 में 114.70 लाख हेक्टेयर हो गया। खरीफ फसलों का कुल उत्पादन जहां 99.28 लाख टन था 2012 में बढ़कर 141.16 लाख टन हो गया। खरीफ फसलों की उत्पादकता सामान्यतः 954 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर आंकी गई थी जो 2012 में बढ़कर 1214 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गई वर्ष 2008 में 8.89 लाख क्विंटल खरीफ फसलों के बीजों का वितरण किया गया था जो 2012-13 में बढ़कर 17.65 लाख क्विंटल हो गया। रबी की फसलों का कुल क्षेत्रफल 2011-12 में 98.24 लाख हेक्टेयर अनुमान लगाया गया था जो बढ़कर 2012-13 में 103.90 लाख हेक्टेयर हो गया। रबी फसलों का कुल उत्पादन वर्ष 2012-13 में 154.89 लाख टन अनुमानित था जो बढ़कर 191.69 लाख टन हो गया। 2011-12 में रबी की फसलों की कुल उत्पादकता 1577 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर अनुमानित थी जो 2012-13 में 1845 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गई।

पूर्व साहित्य का अवलोकन – कृषि लागत एवं कृषक वर्ग पर वर्तमान शोध के पूर्व भी अनेक शोध कार्य संपादित किए गए हैं उन सबका उल्लेख करना न तो यहां संभव है और न ही समाचीन। फिर भी, कतिपय शोधों का उल्लेख करना आवश्यक है ताकि अनुसंधान की पुनरावृत्ति न हो।

आर. एस. देशपांडे एवं टी. रावेन्द्र नायक (2002) – प्रस्तुत अध्ययन में कर्नाटक की प्रमुख फसलों का एम.एस.पी. के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में यह पाया गया कि कृषि तकनीक में परिवर्तन, उत्पादन, उत्पादकता एवं फसल पद्धति में परिवर्तन एम. एस.पी. के कारण हुआ है। परन्तु अध्ययन में यह भी पाया गया कि कृषि तकनीकी एवं कृषि विकास, मूल्यों के अलावा अन्य उपकरणों पर भी निर्भर करता है।

माजिद ए. (1963) – फसल पद्धति और बोए गए क्षेत्र के आकार के बारे में अध्ययन किया और इन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि बोये गए क्षेत्र का आकार नकदी फसल और खाद्य फसल का वितरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कारक है। बड़े किसान नकदी फसल को बड़े स्तर पर बोया करते थे, तथा छोटे और मध्यम किसान उसे कम क्षेत्र में बोया करते थे। जसदनवाला जेड. वाय. (1966) – द्वारा अपने अध्ययन में गांव से विपणन केन्द्र की दूरी का फसल पद्धति पर प्रभाव का विश्लेषण किया। यह प्रभाव खेतों के आकार के प्रभाव से ज्यादा महत्वपूर्ण पाया गया। अग्रवाल के.जी. और गौर एस.एस. (1968) – मध्यप्रदेश में भूमि उपयोग पद्धति में बदलाव 1956-1964 तक का अध्ययन किया है। इस अध्ययन काल के दौरान भले ही पड़ती क्षेत्र के आकार में कमी आई है लेकिन सकल बोये गये क्षेत्र में विकास दर संतोषजनक नहीं रही है।

गिरि आर. (1969) – पंजाब में भूमि पद्धति में बदलाव का अध्ययन किया। इन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि विकास की दर प्रतिवर्ष 1.15 प्रतिशत से बढ़ रही है। कृषि अर्थशास्त्र एवं खेत प्रबंध विभाग, जे.एन.वी.वी. जबलपुर (1977) – इस विभाग ने मध्यप्रदेश में 1956-57 से लेकर 1972-73 तक फसल पद्धति की गतिशीलता का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया कि खाद्य फसल और दालों के

लिए उपयोग किया गया क्षेत्र 15.86 लाख हेक्टेयर और 7.43 लाख हेक्टेयर क्रमशः बढ़ा है। जैन जे. और लाल एस. (1980) – सीहोर जिले में छोटे किसानों की फसल पद्धति का अध्ययन किया। इन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि अनाज और दालों के उत्पादन के लिए जो क्षेत्र इस्तेमाल किया गया वह क्षेत्र संपूर्ण बोगे गए क्षेत्र का 94.07 प्रतिशत था, और जो क्षेत्र नकदी फसलों के लिए इस्तेमाल किया गया, संपूर्ण क्षेत्र का 5.9 प्रतिशत था।

शोध विधि— शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनेक प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण करके विभिन्न आधारों पर व्यापक निष्कर्ष निकालना सम्मिलित है। इस प्रक्रिया में पूछताछ, जांच, गहन निरीक्षण, योजनाबद्ध अध्ययन सोद्देश्य एवं तत्परता युक्त सामान्य निर्धारण आदि की प्रक्रियायें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शोध की प्रकृति चाहे जो भी हो प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित पद्धतियों एवं प्रविधियों का उपयोग करता है। वस्तुतः पद्धति किसी कार्य को पूर्ण करने का व्यवस्थित तरीका है। बिना किसी विशिष्ट पद्धति के सत्य तक पहुंचना कठिन है। इसलिए इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने लिखा है, “सत्य तक पहुंचने के लिए कोई संक्षिप्त पथ नहीं है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा।”² शोध एक विस्तृत व जटिल प्रक्रिया है इसकी सफलता हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि वह शोध के प्रमुख चरणों को दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्थित कार्य करे।

शोध के उद्देश्य

1. सर्वशिक्षित जिलों के कृषकों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रभावों का विश्लेषण करना।
2. सर्वशिक्षित जिलों के कृषि विकास पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रभावों का अध्ययन करना।
3. यह परीक्षण करना कि क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं फसल कटाई मूल्य में कोई संबंध है।

अध्ययन क्षेत्र एवं निदर्शन— इस विधि के आधार पर शोधार्थी ने प्रदेश के दो जिलों को विचारपूर्वक चयन किया। दमोह एवं नरसिंहपुर दोनों जिले प्रदेश के फसलीय विभाजन में गेहूँ उत्पादक क्षेत्र में हैं। दमोह कम उत्पादकता वाला जिला एवं नरसिंहपुर उच्च उत्पादकता वाला जिला है। परन्तु दोनों जिले एक ही फसलीय क्षेत्र में आते हैं। प्रत्येक जिले से दो-दो तहसीलों का चयन भी शोधार्थी द्वारा विचारपूर्वक किया गया है। चयनित तहसीलों में से प्रत्येक तहसील से एक-एक गांव का चयन विचारपूर्वक किया गया। गांव का चयन करते समय शोधार्थी ने एक गांव तहसील मुख्यालय के पास 5-10 कि.मी. की दूरी पर और एक गांव 20-25 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं चयन किये गये। इस तरह से दोनों जिलों की दो-दो तहसीलों से एक-एक गांव का चयन किया गया। शोधार्थी ने कुल चार गांवों का अध्ययन किया जिनमें दो गांव तहसील मुख्यालय के पास व दो गांव तहसील मुख्यालय से दूर स्थित हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में प्रत्येक गांव से 25-25 किसानों का चयन किया गया। किसानों के चयन में भी शोधार्थी ने सविचार निदर्शन का उपयोग किया। चूंकि न्यादर्थ कम होने के कारण हमने बृहद व मध्यम किसानों के एक ही श्रेणी में रखा है। अध्ययन की सुविधा हेतु उक्त दोनों वर्गों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। प्रत्येक कृषक वर्ग में किसानों के चयन में दैव निदर्शन विधि का उपयोग किया गया है। हमने दैव आधार पर किसानों का चयन किया है। प्रत्येक सर्वशिक्षित ग्राम में जोतों की सीमा में विभिन्नता देखी गई परन्तु यह हमारी मानक सीमा को प्रभावित नहीं कर पाई इसलिए हमने अध्ययन की सुविधा हेतु औसतों का ही उपयोग किया है।

समंक विश्लेषण

कृषि कीमतों में तेज वृद्धि एवं अधिक उच्चावचन के कई बुरे प्रभाव पड़ते हैं। किसी भी फसल की कीमत में तेज गिरावट से उसके उत्पादकों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनकी आय में तेजी से कमी होती है और अगले वर्ष वे उस फसल को बोने से हिचकिचाते हैं। यदि यह फसल आम जनता के उपभोग की वस्तु है तो अगले वर्ष पूर्ति मांग की अपेक्षा कम रहने की संभावना होती है और इस अंतराल को पूरा करने के लिए सरकार को आयात करने पड़ेगे यदि कृषि वस्तु के उपयुक्त भंडार नहीं हैं तब। इसके विपरीत यदि किसी फसल की कीमत किसी वर्ष बहुत बढ़ जाती है तो उपभोक्ताओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि यह वस्तु उपभोग की आवश्यक वस्तु है तो उपभोक्ता उसे खरीदने के लिए अन्य वस्तुओं के खर्च कम करना पड़ेगा। इसका अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।¹ न्यूनतम समर्थन कीमतों तथा वसूली कीमतों का निर्धारण करते समय सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादकों को उत्पादन करने की प्रेरणा बनी रहे, अर्थात् कीमत ऐसे स्तर पर निर्धारित की जाए जो किसानों को और ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकें। कृषि क्षेत्र में केवल आय व कीमत स्थिरीकरण उद्देश्य नहीं है अपितु इसका प्रयोग संवृद्धि के एक अस्त्र के रूप में करना है।¹

योजनाकाल में भारत में कृषि मूल्यों में परिवर्तनों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कृषि मूल्यों में स्थिरता नहीं रही है। प्रथम योजना में जहां कृषि मूल्य 23 प्रतिशत गिरे वहीं इसके बाद के वर्षों में खाद्यान्न के मूल्यों में 6-10 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई। कृषि मूल्यों में परिवर्तन की इस प्रवृत्ति से संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। सरकार कृषि मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करने तथा मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं निकासी मूल्य घोषित करती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि उत्पादनों के मूल्यों में परिवर्तन अनेक कारणों से होते हैं जैसे कृषि उत्पादन में परिवर्तन, उपभोग में कमी या वृद्धि सट्टेबाजी की प्रवृत्ति, व्यापार चक्र, आयात-निर्यात आदि। कृषि मूल्य नीति के अंतर्गत इन्हीं कारणों का अध्ययन किया जाता है तथा उन उपायों को अपनाया जाता है जिससे मूल्यों को स्थिरता प्रदान की जा सके। कृषि वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता रहने से जहां एक ओर कृषकों को उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहन मिलता है वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास को गति मिलती है। इससे बचत, विनियोग व पूंजी निर्माण को पर्याप्त सहयोग मिलता है।

तालिका क्र.1. मध्यप्रदेश में प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति क्वि.)

फसलों के नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
धान	880	1080	1080	1110	1280	1345
मक्का	840	840	880	980	1175	1310
गेंहू	1000	1130	1200	1220	1285	1350
चना	1600	1760	2100	2800	3000	3100
सोयाबीन	1390	1390	1440	1690	2240	2560

स्रोत – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और कृषि संचालनालय म.प्र.।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2008-09 में 880 रुपये प्रति क्विंटल था जो 2009-10 में बढ़कर 1080 रुपये प्रति क्विंटल हो गया तथा 2013-14 में बढ़कर 1345 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। मक्का का समर्थन मूल्य 2008-09 में 840 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। गेंहू का समर्थन 2008-09 में 1000 रुपये प्रति क्विंटल था जो 2013-14 में बढ़कर 1350 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। वर्ष 2008-09 में चने का समर्थन मूल्य 1600 रुपये प्रति क्विंटल था जो 2013-14 में लगभग दोगुना हो गया यह 3100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। सोयाबीन 2008-09 में 1390 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2013-14 में 2560 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि देखी गई जो यह स्पष्ट करता है कि सरकार ने मूल्यों में व लागत में हो रही वृद्धि के साथ-साथ मंहगें कृषि निवेश को भी ध्यान में रखा है।

तालिका क्र.2. मध्यप्रदेश में चावल और गेंहू के न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रवृत्ति

वर्ष	चावल का उपनाति मूल्य	गेंहू का उपनाति मूल्य
2007-08	918	1037.85
2008-09	1002.60	1101.75
2009-10	1087	1165.55
2010-11	1171.40	1229.45
2011-12	1255.79	1293.25
2012-13	1340.21	1357.15
N = 6	Yc = 6775	Yc = 7185

स्रोत – तालिका क्र.1 के आधार पर ज्ञात किया गया है।

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चावल और गेंहू के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है। चावल का उपनाति मूल्य 2007-08 में जहाँ 918 रुपये प्रति क्विंटल था यह 2012-13 में 1340.21 रुपये प्रति क्विंटल देखा गया दीर्घकाल में इसकी बढ़ने की प्रवृत्ति है। दूसरी ओर गेंहू की मूल्य में भी वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है यह 2007-08 में 1037.85 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2012-13 में 1357.12 रुपये प्रति क्विंटल देखी गई। चावल और गेंहू की प्रवृत्ति बढ़ती हुई है परन्तु गेंहू की तुलना में चावल के मूल्यों में अधिक वृद्धि की प्रवृत्ति है।

तालिका क्र.3. मध्यप्रदेश में प्रमुख फसलों का कटाई मूल्य (FHP) (रु. प्रति क्वि.)

फसल	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
चावल	1583	1602	1606	1710	1730
मक्का	762	851	918	990	1000
तुअर	2724	3546	3514	3580	3588
गेंहू	1149	1236	1166	1206	1240
चना	2151	2005	2281	2310	2370

स्रोत – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और कृषि संचालनालय म.प्र.।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विभिन्न फसलों की कटाई मूल्य (FHP) में वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। वर्ष

2008-09 में चावल का कटाई मूल्य 1583 रुपये प्रति क्विंटल था जो 2012-13 में बढ़कर 1730 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। वर्ष 2009-10 की तुलना में 2010-11 में कटाई मूल्य में नाममात्र की वृद्धि देखी गई। मक्का जहां 2008-09 में 762 रुपये प्रति क्विंटल था वहीं 2012-13 में बढ़कर 1000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तुअर 2724 रुपये प्रति क्विंटल थी जो बढ़कर 2012-13 में 3588 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। वर्ष 2008-09 में गेहू का मूल्य 1149 रुपये प्रति क्विंटल व चने का मूल्य 2151 रुपये प्रति क्विंटल था जो 2012-13 में बढ़कर क्रमशः 1240 व 2370 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। फसल कटाई मूल्य इन पांच वर्षों में प्रत्येक फसल में बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ है। चावल, मक्का और तुअर का फसल कटाई मूल्य 2005-06 से 2012-13 तक लगभग दोगुना हो गया।⁸

तालिका क्र.4. मध्यप्रदेश में प्रमुख फसलों की थोक बिक्री कीमत गेहू व चावल (रु. प्रति क्वि.)

फसल	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
गेहू	1128	1248	1257	1352	1620
चावल	1196	1200	1064	1106	2070

स्रोत - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और कृषि संचालनालय म.प्र.।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2008-09 में गेहू की थोक बिक्री कीमत 1128 रुपये प्रति क्विंटल थी जो 2010-11 में बढ़कर 1257 हो गई एवं 2012-13 में 1620 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। वहीं चावल का थोक बिक्री मूल्य 2008-09 में 1196 रुपये प्रति क्विंटल था जो 2010-11 में कम होकर 1064 रुपये प्रति क्विंटल हो गया तथा 2011-12 में पुनः 1156 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। 2012-13 में थोक बिक्री मूल्य में भारी वृद्धि देखने को मिलती है। यह एक ही वर्ष में लगभग दोगुना होकर 2070 रुपये प्रति क्विंटल हो गया।⁹

तालिका क्र.5. मध्यप्रदेश में चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल कटाई मूल्य एवं थोक मूल्य (वृद्धि दर)

वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य	फसल कटाई मूल्य	थोक मूल्य
2008-09	18.12	0.19	0.50
2009-10	22.72	1.20	0.33
2010-11	0	0.24	-11.33
2011-12	2.77	6.47	3.85
2012-13	15.31	1.16	87

स्रोत - न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल कटाई मूल्य एवं थोक मूल्यों पर आधारित।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि दर वर्ष 2008-09 में लगभग 18.12 प्रतिशत थी जो फसल कटाई वृद्धि दर 0.19 एवं थोक मूल्य की वृद्धि दर 0.50 से बहुत अधिक थी। वर्ष 2010-11 में न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि दर शून्य थी जबकि फसल कटाई वृद्धि दर इसी वर्ष 0.24 प्रतिशत थी व थोक मूल्य की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। वर्ष 2012-13 में चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि दर लगभग 15.31 प्रतिशत थी जबकि फसल कटाई मूल्य में वृद्धि दर 1.16 प्रतिशत थी व थोक मूल्य की वृद्धि दर में आश्चर्यजनक रूप से तेजी आई और यह लगभग 87 प्रतिशत बढ़ गई। फसल कटाई और थोक मूल्य की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की दर तुलनात्मक रूप से अधिक है।

तालिका क्र.6. मध्यप्रदेश में गेहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल कटाई मूल्य एवं थोक मूल्य (वृद्धि दर)

वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य	फसल कटाई मूल्य	थोक मूल्य
2008-09	29.41	2.11	1.86
2009-10	2.72	7.57	10.63
2010-11	6.19	-5.66	0.72
2011-12	1.66	3.43	7.55
2012-13	5.32	2.81	19.82

स्रोत - न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल कटाई मूल्य एवं थोक मूल्यों पर आधारित।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2008-09 में पूर्व वर्ष की तुलना में 29.41 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई जबकि फसल कटाई वृद्धि दर में 2.11 प्रतिशत व थोक मूल्य में 1.86 प्रतिशत वृद्धि देखी गई। वर्ष 2011-12 में न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.66 प्रतिशत की वृद्धि दर हुई जबकि फसल कटाई वृद्धि दर 3.43 प्रतिशत की वृद्धि पूर्व वर्ष की तुलना में हुई वहीं थोक मूल्य में 7.55 प्रतिशत वृद्धि हुई। फसल कटाई वृद्धि दर व थोक मूल्य की तुलना में इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर कम रही। वर्ष 2012-13 में न्यूनतम समर्थन की वृद्धि दर 5.32 प्रतिशत थी जो फसल कटाई के 2.81 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी परन्तु थोक मूल्य में 19.82 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि की तुलना में कम थी। गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल कटाई व थोक मूल्य में वर्ष 2008-09 से अब तक भारी उच्चावचन देखने को मिलता है।

थोक मूल्य सूचकांक पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का प्रभाव

न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष फसलीय मौसम के प्रारंभ में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा कृषि लागत के अनुमान के बाद घोषित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि ही होती है परन्तु वृद्धि की प्रवृत्ति भिन्न हो सकती है।

तालिका क्र.7. गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं थोक मूल्य सूचकांक

वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य	वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन न्यूनतम समर्थन मूल्य में	प्रतिशत परिवर्तन आधार, वर्ष 2005-06 के आधार पर	थोक मूल्य सूचकांक	थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक परिवर्तन	थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन आधार पर 2005-06 के आधार पर
2005-06	650	—	—	105	—	—
2006-07	750	15.38	15.38	125	19.05	19.05
2007-08	1000	33.33	53.85	134	7.2	27.62
2008-09	1080	8	66.15	148	10.45	40.95
2009-10	1100	1.85	69.23	166	12.11	58.10
2010-11	1170	6.36	80	171	3.01	62.86
2011-12	1285	9.83	97.69	168	-1.75	60

स्रोत – www-rbi.org.in, Economic survey 2012-13, annexure A 67-68.

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्ष 2006-07 में 15.38 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 33 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई। गेहूँ का थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2006-07 में 19.05 प्रतिशत व 2007-08 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 97 प्रतिशत बढ़ गया। 2005-06 से 2011-12 की अवधि में जबकि थोक मूल्य सूचकांक में इसी अवधि में 60 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है।¹⁰

तालिका क्र. 8 .चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं थोक मूल्य सूचकांक

वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य	वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन न्यूनतम समर्थन मूल्य में	प्रतिशत परिवर्तन आधार, वर्ष 2005-06 के आधार पर	थोक मूल्य सूचकांक	थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक परिवर्तन के आधार पर	थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन आधार पर 2005-06 के आधार पर
2005-06	570	—	—	105	—	—
2006-07	580	1.75	1.75	110	4.76	4.76
2007-08	645	11.21	13.16	122	10.91	16.19
2008-09	850	31.78	49.12	141	15.57	34.29
2009-10	950	11.76	66.67	158	12.06	50.48
2010-11	1000	5.26	75.44	167	5.70	59.05
2011-12	1080	8	89.47	172	2.99	63.81

स्रोत – www-rbi.org.in

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2005-06 से 2011-12 की अवधि में चावल के समर्थन मूल्य में 89.47 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई वहीं थोक मूल्य सूचकांक में 63.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि की तुलना में कम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को आमतौर पर उनके संबंधित थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के साथ समान रूप से देखा जाता है। परन्तु इसके विपरीत गेहूँ का थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2011-12 के मध्य 1.75 प्रतिशत कम हुआ है जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 9.83 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है।¹¹

तालिका क्र. 9. न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं थोक मूल्य सूचकांक में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर (2006-12)

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य	थोक मूल्य सूचकांक
चावल	12.53	8.35
गेहूँ	11.62	8.66

स्रोत – www-rbi.org.in

न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य वस्तुओं की मुद्रा स्फीति के बीच सहसंबंध पर विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। मौद्रिक नीति 2012-13 के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि स्फीति के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादातर वस्तुओं के बाजार मूल्य में वृद्धि का कारण बन रही है। ICRIER के एक अनुसंधान के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रत्यक्ष प्रभाव थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि करता है वहीं यह अप्रत्यक्ष प्रभाव भी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि थोक मूल्य मुद्रा स्फीति के लिए एक मंजिल के रूप में कार्य करता है और सभी की उम्मीदों के अनुरूप यह खाद्य कीमतों में वृद्धि करता है।¹²

तालिका क्र. 10. न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं फसल कटाई मूल्य में सहसंबंध

क्र.	फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य/फसल कटाई मूल्य सहसंबंध
1	गेहूँ	0.86
2	चावल	0.60
3	मक्का	0.50
4	चना	0.31

नोट – सहसंबंध गुणांक प्रामाणिक विभ्रम की सीमा के मध्य है।

फसल कटाई मूल्य व न्यूनतम समर्थन मूल्य में सहसंबंध, न्यूनतम समर्थन मूल्य का बाजार कीमत के प्रभाव की ओर संकेत करता है। यह संकेत करता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार कीमत प्रवृत्ति में प्रमुख भूमिका अदा करता है। हमने यह पाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व फसल कटाई मूल्य में गेहूँ में सहसंबंध सर्वाधिक पाया गया है और अन्य फसलों में सहसंबंध न्यूनतम पाया गया है। जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल कटाई मूल्य के संबंधों में न्यूनता है वहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रभावी भूमिका पर प्रश्न खड़ा होता है।¹³

तालिका क्र.11. लागत, उत्पादकता एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (दमोह) (उत्तरदाताओं का प्रतिशत)

	उत्पादकता/हेक्ट.	न्यूनतम समर्थन मूल्य / क्विंटल*	लागत प्रति हेक्ट.
गेहूँ	24.87	1450	40291
चना	9.54	3000	33695
चावल	11.44	1345	36901

स्रोत – स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर, 'कृषि सांख्यिकी म.प्र. कृषि संचालनालय, भोपाल, पृ.137

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दमोह जिले में गेहूँ की उत्पादकता 24.87 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जबकि लागत 40251 रुपये प्रति हेक्टेयर है। वहीं प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपये है। चना की उत्पादकता 9.54 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है जबकि लागत 36659 रुपये प्रति हेक्टेयर है व समर्थन मूल्य 3000 रुपये प्रति क्विंटल है। चावल की उत्पादकता जिले में 11.44 क्विंटल

प्रति हेक्टेयर है जबकि कुल लागत 36901 रुपये प्रति हेक्टेयर है और चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1345 रुपये प्रति विंटल है। तालिका के अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि गेहूँ की लागत सर्वाधिक है जबकि गेहूँ की उत्पादकता भी अधिक है परन्तु समर्थन मूल्य कम होने के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं चना की लागत गेहूँ की तुलना में 33659 रुपये प्रति हेक्टेयर है जबकि समर्थन मूल्य गेहूँ की तुलना में लगभग दो गुना है और गेहूँ की तुलना में चना की उत्पादकता भी कम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में यदि और वृद्धि होती है तथा निश्चित रूप से गेहूँ का उत्पादन और अधिक बढ़ेगा।

तालिका क्र.12. उत्पादन, उत्पादकता एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (नरसिंहपुर)

	उत्पादकता/हेक्ट.	न्यूनतम समर्थन मूल्य /विंटल*	लागत प्रति हेक्ट.
गेहूँ	34.3	1450	40683
चना	12.05	3000	34005
चावल	19.71	1345	37118

स्रोत – स्वयं के सर्वेक्षण के आधार पर, 'कृषि सांख्यिकी म.प्र. कृषि संचालनालय, भोपाल, पृ.137

नरसिंहपुर जिले में गेहूँ की उत्पादकता 34.3 विंटल प्रति हेक्टेयर है जबकि गेहूँ की लागत 40683 रुपये प्रति हेक्टेयर है। वहीं चना और चावल की उत्पादकता क्रमशः 12.05 और 19.71 है जबकि लागत 34005 एवं 37118 रुपये प्रति हेक्टेयर है। जिले में गेहूँ की लागत सर्वाधिक है उत्पादकता भी सर्वाधिक है। जबकि चना और धान की उत्पादकता गेहूँ की तुलना में कम है लागत भी गेहूँ की तुलना में कम है। दमोह जिले की तुलना में नरसिंहपुर जिले में गेहूँ की उत्पादकता अधिक है जबकि लागत कम है। चना और चावल की उत्पादकता भी दमोह की तुलना में अधिक है। दमोह की तुलना में नरसिंहपुर के किसान अधिक लाभ की स्थिति में हैं।

कृषि लागत :-

कृषि से आय का अनुमान विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। यह अनुमान न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण, कीमतों में नियंत्रण व स्थायित्व तथा कृषकों की प्रेरणा, प्रबंध व मात्रा का प्रतिपादन करने में सहायक होते हैं। लागतों में वृद्धि और निम्न मौद्रिक प्रतिफल के कारण कृषि निम्न मौद्रिक प्रतिफल वाला क्षेत्र बन गया है। इसके अनेक व्यक्ति व समाष्टित कारण हैं। प्रस्तुत अध्याय प्रमुख फसलों की लागत व आय का अनुमान प्रदर्शित करता है। यह प्रमुख फसलों की खेती के अर्थशास्त्र पर केन्द्रित है। सामान्यतः लागत और प्रतिफल जोत के आकार के साथ परिवर्तित होती रहने की संभावना होती है। इसलिए हमारा विश्लेषण प्रमुख फसलों के अर्थशास्त्र व जोतों के आकार पर केन्द्रित है।

लागत व आय के अनुमान हेतु जिले की प्रत्येक तहसील से एक गांव प्रतिनिधि गांव के रूप में अध्ययन हेतु चयन किया गया। चयनित प्रत्येक गांवों से दस किसानों का अध्ययन किया। अध्ययन में सर्वेक्षित ग्रामों में सकल उत्पादन के मूल्य में अंतर देखने को मिला। प्रति हेक्टेयर कुल काश्त लागत व शुद्ध आय में भी अंतर दृष्टिगत होता है। जिले की प्रत्येक तहसील में लगभग 43650 सकल उत्पाद मूल्य देखा गया।

तालिका क्र.13. औसत सकल उत्पाद मूल्य, लागत A₂ और प्रति हेक्टेयर शुद्ध आय (इकाई रुपये में)

क्र.	सर्वेक्षित गांव / तहसील	सकल उत्पाद मूल्य/हेक्ट.*	लागत प्रति हेक्ट.*	शुद्ध आय
1	हटा बलेह	43650	42248	1402
2	दमोह कादीपुर	43650	42262	1388
3	करेली बहेरिया	57780	41240	16540
4	गाडरवारा बसुरिया	57780	41200	10100

स्रोत – स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।, नोट : '5 प्रतिशत सार्थकतास्तर पर t (Calculated value) > t (tabulated value) है अतः अंतर सार्थक है।

तालिका अवलोकन से ज्ञात होता है कि दमोह जिले की हटा तहसील के बलेह ग्राम में कुल सकल उत्पादन मूल्य 43650 रुपये प्रति हेक्टेयर है। जबकि लागत 42248 रुपये प्रति हेक्टेयर है। शुद्ध आय 1402 रुपये प्रति हेक्टेयर है। वहीं जिले की दमोह तहसील के कादीपुर ग्राम में 43650 रुपये प्रति हेक्टेयर सकल उत्पाद मूल्य और 42262 रुपये प्रति हेक्टेयर लागत हैं शुद्ध आय 1388 रुपये है। वहीं नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील के बहेरिया ग्राम में 57780 रुपये प्रति हेक्टेयर सकल उत्पाद का मूल्य है जबकि लागत 41240 रुपये

प्रति हेक्टेयर है। यहां किसानों की शुद्ध आय, 16540 रुपये है। स्पष्ट है कि यह दमोह जिले की दोनों तहसीलों से कहीं अधिक है। गाड़रवारा तहसील के वसुरिया ग्राम में उत्पाद का मूल्य 5778 रुपये प्रति हेक्टेयर है जबकि लागत 41200 रुपये प्रति हेक्टेयर है। शुद्ध आय 10100 रुपये है। दमोह की तुलना में नरसिंहपुर के किसानों की शुद्ध आय लगभग 34 प्रतिशत अधिक है। इसका कारण दमोह की तुलना में नरसिंहपुर जिले में कृषि उत्पादकता अधिक है। नर्मदा घाटी एवं अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी होने के कारण कृषि उत्पादन बहुत अधिक होता है। इसलिए नरसिंहपुर के किसान दमोह के किसानों की तुलना में अधिक लाभ कमाते हैं।

तालिका क्र. 14. भूमि आवंटन एवं फसलीय क्षेत्र में वृद्धि का निर्णय दमोह (उत्तरदाताओं का प्रतिशत)

मद	फसलीय क्षेत्र में वृद्धि के कारण	
	गेहूँ	धान
पिछले वर्ष की कीमत	70	50
पिछले 3 वर्षों की औसत कीमत	70	50
कीमत उच्चावचन	10	15
अन्य प्रतियोगी फसलों की कीमतें	60	65
घर में उपयोग हेतु	15	20
बाजार तंत्र की अनुपलब्धता के कारण	20	25
एम.एस.पी. के कारण	80	70
आदानों की उपलब्धता के कारण	75	78

स्रोत – स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भूमि आवंटन एवं फसलीय क्षेत्र में वृद्धि का निर्णय में न्यूनतम समर्थन मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लगभग 80 प्रतिशत किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण फसलीय क्षेत्र में वृद्धि की है वहीं 70 प्रतिशत किसानों ने धान के फसलीय क्षेत्र में वृद्धि की है। लगभग 70 प्रतिशत किसानों ने गेहूँ के क्षेत्र में वृद्धि पिछले वर्ष की कीमतों को ध्यान में रखकर की है। धान में लगभग 50 प्रतिशत किसानों ने पिछले वर्ष की कीमत को ध्यान में रखकर फसलीय क्षेत्र में वृद्धि की है। फसलीय क्षेत्र में वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक अन्य प्रतियोगी फसलों की कीमतें भी रही है। आदानों की उपलब्धता के कारण भी फसलीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है। हम कह सकते हैं कि फसलीय क्षेत्र में वृद्धि करने के निर्णय में न्यूनतम समर्थन मूल्य ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

तालिका क्र. 15. भूमि आवंटन एवं फसलीय क्षेत्र में वृद्धि का निर्णय नरसिंहपुर (उत्तरदाताओं का प्रतिशत)

मद	फसलीय क्षेत्र में वृद्धि के कारण	
	गेहूँ	धान
पिछले वर्ष की कीमत	73	53
पिछले 3 वर्षों की औसत कीमत	71	57
कीमत उच्चावचन	13	1
अन्य प्रतियोगी फसलों की कीमतें	73	68
घर में उपयोग हेतु	11	20
बाजार तंत्र की अनुपलब्धता के कारण	14	22
एम.एस.पी. के कारण	87	77
आदानों की उपलब्धता के कारण	79	75

स्रोत – स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।

नरसिंहपुर जिले में भी भूमि आवंटन एवं फसलीय क्षेत्र में वृद्धि का प्रमुख कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य रहा है। 87 प्रतिशत

लोगों ने गेहूँ के क्षेत्र में व 77 प्रतिशत लोगों ने धान के क्षेत्र में वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण की है। इसके अलावा पिछले वर्ष की कीमतों के कारण 71 प्रतिशत किसानों ने गेहूँ व 53 प्रतिशत किसानों ने धान के क्षेत्र में वृद्धि की है। अन्य प्रतियोगी फसलों की कीमतों के कारण 73 प्रतिशत किसानों ने गेहूँ व 68 प्रतिशत किसानों ने धान के फसलीय क्षेत्र में वृद्धि की है। फसलीय क्षेत्र में वृद्धि का एक बड़ा कारण आदानों की उपलब्धता है लगभग 79 प्रतिशत किसानों ने गेहूँ की फसलीय क्षेत्र में वृद्धि व 75 प्रतिशत किसानों ने धान के क्षेत्र में वृद्धि की है। इस तरह से गेहूँ व धान के फसलीय क्षेत्र में वृद्धि का प्रमुख कारण फसलों की कीमतें ही रही है। कीमतों के ऊँचे होने में न्यूनतम समर्थन मूल्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूक्ष्म स्तर पर कीमत महत्वपूर्ण भूमिका तो अदा करती है परन्तु गैर कीमत प्रभाव भी कृषकों की निर्णय को प्रभावित करते हैं। कृषकों की इस निर्णय प्रक्रिया में गैर कीमत प्रभाव भी उपलब्ध रहती है।

तालिका क्र. 16 न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रति जागरूकता (उत्तरदाताओं का प्रतिशत)

जिला	गेहूँ	चावल	चना
दमोह	80	60	66
नरसिंहपुर	85	72	70

स्रोत – स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दमोह जिले में गेहूँ के समर्थन मूल्य की जानकारी 70 प्रतिशत किसानों को है जबकि चावल व चना के समर्थन मूल्य की जानकारी क्रमशः 60 व 66 प्रतिशत किसानों को है। वहीं नरसिंहपुर जिले में गेहूँ की समर्थन मूल्य की जानकारी 85 प्रतिशत किसानों को, चावल की 72 प्रतिशत व चना की 70 प्रतिशत किसानों को है। दमोह जिले की तुलना में नरसिंहपुर के किसान अधिक जागरूक है।

तालिका क्र. 17. निर्णय क्षमता दमोह/नरसिंहपुर (उत्तरदाताओं का प्रतिशत)

निर्णय	सीमांत	लघु	मध्यम	बड़े	सभी
क्या नकद आदान में वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण होती है।	60	72	83	90	92
क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किराये पर लिए गए श्रम की मजदूरी दर में वृद्धि होती है।	98	90	92	90	94
क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से नई तकनीक का उपयोग बढ़ा है।	30	96	85	86	85
क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से बाजार के समय में वृद्धि हुई है।	02	07	05	07	10
क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से बाजार के स्थान में परिवर्तन करते हैं।	30	32	28	25	30
क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से अन्य निवेश करते हैं।	10	12	14	10	12

स्रोत – स्वयं के सर्वेक्षण पर आधारित।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 92 प्रतिशत किसान नकद आदान में वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण होती है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण किराये पर लिए गए श्रम की मजदूरी की दर में वृद्धि हो जाती है। 85 प्रतिशत किसान कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण नई तकनीक का उपयोग बढ़ा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण बाजार के समय में विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। बाजार के स्थान में भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण बड़े किसानों में नई तकनीक का उपयोग बढ़ा है, छोटे व मझोले किसानों में भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ा है। परन्तु सीमांत किसानों में नई तकनीक का उपयोग कम देखने को मिला। किराये पर लिए गए श्रमिकों की मजदूरी की दर में वृद्धि प्रत्येक कृषक वर्ग में देखने को मिलती है।

किसानों की निर्णय प्रक्रिया में कीमत निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परन्तु केवल एमएसपी ही नहीं अन्य तथ्य भी महत्वपूर्ण है। अभी भी सारे किसान एमएसपी के प्रति जागरूक नहीं हैं न ही इसका बेहतर लाभ ले पा रहे हैं। पिछले दशक के अनुभव से पता चलता है कि बाजार कीमत प्रवृत्तियों से फसल पद्धति, फसल किस्मों और प्रौद्योगिकी निर्धारित होती है। कृषि लागत से यह ज्ञात होता है कि कृषक वास्तव में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक व्यय करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की निर्णय क्षमता को यदि पहचान लेता है तब यह कृषक कल्याण में एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध हो सकता है।

परिकल्पना परीक्षण (H_{01}) –: प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण सर्वेक्षण के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं सरकारी मूल्य नीति का कृषि अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है। विकास पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है। विकास मापदण्डों, वितरण पहलुओं, पर्यावरण प्रभाव व संसाधनों के आवंटन में निर्णय के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य नीति के प्रभावी क्षेत्र के रूप में सामने आई है। प्रस्तुत अध्ययन में हमने सात परिकल्पनाएँ ली थी। हमारी सभी परिकल्पनाएँ सत्य सिद्ध हुई हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं फसल कटाई मूल्य में सकारात्मक संबंध देखा गया है। कृषक

उत्पादन की बिक्री के समय न्यूनतम समर्थन मूल्य का ध्यान रखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण जिलों में उन्नत कृषि तकनीक के उपयोग में वृद्धि हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की भूमि आवंटन एवं फसलीय क्षेत्र में भी वृद्धि देखने को मिलती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं कृषि उत्पादन में भी सीधा संबंध देखने को मिलता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रति किसान जागरूक हैं। परन्तु इसका लाभ बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। हमारी परिकल्पनाओं का परीक्षण एवं विश्लेषण निम्नवत है—

प्रथम परिकल्पना(H₀₂) — न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं फसल कटाई मूल्य में सकारात्मक संबंध है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल कटाई मूल्य में सकारात्मक संबंध पाया गया। हमने चार प्रमुख फसलों गेहूँ, मक्का, धान एवं चना के न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं फसल कटाई मूल्य का सहसंबंध ज्ञात किया। गेहूँ का सहसंबंध 0.86 पाया गया वहीं चावल, मक्का, चना का सहसंबंध क्रमशः 0.60, 0.50 एवं 0.31 पाया गया। सहसंबंध का प्रमाप विभ्रम निकालने पर गेहूँ की उच्चतम सीमा 0.91 एवं निम्नतम सीमा 0.80 है। गेहूँ सहसंबंध 0.86 है जो प्रमाप विभ्रम की सीमा के मध्य है। चावल की प्रमाप विभ्रम की उच्चतम सीमा 0.729 एवं निम्नतम सीमा 0.47 है। चावल का सहसंबंध भी 0.60 प्रमाप विभ्रम की सीमा के मध्य है। मक्का के प्रमाप विभ्रम की उच्चतम सीमा 0.59 एवं निम्नतम सीमा 0.401 है जबकि मक्का का सहसंबंध 0.50 है जो प्रमाप विभ्रम की सीमा के मध्य पाया गया है। चना की प्रमाप विभ्रम की उच्चतम सीमा 0.43 है व निम्नतम सीमा 0.162 है जबकि चना के मूल्यों का सहसंबंध 0.31 है जो प्रमाप विभ्रम की सीमा के मध्य पाया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परीक्षण उपरान्त उपरोक्त चारों फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं फसल कटाई मूल्य के मूल्यों में सहसंबंध सार्थक है।

सुझाव —:

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण के आधार पर हम जिले में विपणन व्यवस्था में सुधार हेतु निम्न सुझाव दे सकते हैं—

1. किसानों को एक निश्चित समर्थन मूल्य की गारंटी देना ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके, उत्पादन में जोखिम न रहे और वे लोग उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए निवेश को तत्पर रहे।
2. योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप विभिन्न फसलों के उत्पादन को निर्देशित किया जाना चाहिए।
3. अधिक आगतों के प्रयोग द्वारा उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों व अन्य आगतों का प्रयोग करने वाली नई कृषि तकनीक के और प्रसार द्वारा कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है।
4. किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे खाद्यान्नों का बढ़ता हुआ हिस्सा बाजार में बेचने के लिए तैयार हों।
5. अत्याधिक कीमत वृद्धि से उपभोक्ताओं की रक्षा करना, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं की उन वर्षों में जब आपूर्ति मांग से काफी कम हो और बाजार कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही हो।
6. जिले में कृषि विपणन में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादों के श्रेणी विभाजन तथा प्रभावीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे कृषक को अपनी उपज का उचित मूल्य तो मिलता है। बाजार का विस्तार होता व उपज में सुधार होता है।

संदर्भ सूची

1. मिश्रा पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, 2010, पृ. 370।
2. Govt. of India agriculture Pricing Policy in India, 1963 quoted from C.S. Venkatram in c.h.shah Agriculture Development in India, p.211-213.
3. पी.डी. महेश्वरी, एवं शीलचन्द्र गुप्ता, भारतीय आर्थिक नीति, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, 2008, पृ. 256।
4. पी.डी. महेश्वरी, एवं शीलचन्द्र गुप्ता, भारतीय आर्थिक नीति, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, 2008, पृ. 257।
5. पी.डी. महेश्वरी, एवं शीलचन्द्र गुप्ता, भारतीय आर्थिक नीति, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, 2008, पृ. 258।
6. Economic Survey, Government of India, 2012-13, p. 180.
7. कृषि सांख्यिकी, 2010 मध्यप्रदेश कृषि संचालनालय, भोपाल, पृ. 137।
8. कृषि सांख्यिकी, 2010 मध्यप्रदेश कृषि संचालनालय, भोपाल, पृ. 136।
9. www.agmarket.in
10. www.cacp.dacnet.nic.in
11. www.cacp.dacnet.nic.in
12. Agriculture produce Pricing Policy, Loaksabha Secritiate member reference, 2013, p.9
13. R.S. Deshpandey, T. Raviendra Naika, Impact of Minimum Support Price on Agriculture Economy : A study in Karnataka, 2002, p- 58.
14. पी.के., गुप्ता, कृषि अर्थशास्त्र, वृन्दा पब्लिकेशन प्रा. लि., दिल्ली, 1991, पृ. 371
15. पी.के., गुप्ता, कृषि अर्थशास्त्र, वृन्दा पब्लिकेशन प्रा. लि., दिल्ली, 1991, पृ. 381
16. जिला सांख्यिकी कार्यालय दमोह, म.प्र.
17. दत्त एवं सुन्दरम् भारतीय अर्थव्यवस्था एस.चांद प्रकाशन, 2012, पृ. 572

Publish Research Article International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- * International Scientific Journal Consortium
- * OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.net